ISSN-0970-0718

जागृति

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

वर्ष:60 अंक:5 मुम्बई अप्रैल 2016

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई

ISSN-0970-0718

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की
औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका
वर्ष 60 अंक 5 मुम्बई अप्रैल 2016

अध्यक्ष
अरुण कुमार झा

सम्पादक
के. एस. राव

उप सम्पादक
सुबोध कुमार

अवर उप सम्पादक
अमृता सोम मुखर्जी

अवर हिन्दी अनुवादक
सरस्वती खनका

मुद्रण प्रबंधक
ए. आर. सकलकले

वरिष्ठ कलाकार - अनुप खोडस्कर
कलाकार - दिलीप पालकर

के. सुब्बाराव, द्वारा प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 के लिए प्रकाशित एवं मुद्रित
टेलिफैक्स: 022-26719465
ई-मेल: jagritikvic@gmail.com वेबसाईट: www.kvic.org.in

प्रचार, फिल्म एवं लोक शिक्षण कार्यक्रम निदेशालय, खादी और ग्रामोद्योग आयुक्त कार्यालय, ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई - 400 056 में प्रकाशित
सम्पादक: के. सुब्बाराव राव

वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रू. 100/-
वर्ष के लिये सदस्यता शुल्क	:	रू. 250/-

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा व्यक्त विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा सम्पादक सहमत हों।

इस अंक में...

समाचार सार ....3 से 37

एमएसएमई मंत्री महोदय द्वारा नागालैंड में खादी प्लाजा के लिए 6 करोड़.........
स्टैण्ड-अप इण्डिया पहल के तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी खड़े किये...........
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सुशासन और रोजगार सृजन पर जोर............
वर्ष 2016-17 के दौरान 'पीएमईजीपी' के तहत 4,25,000 से अधिक.........
खादी के स्टोर को दी जायेगी फ्रेंचाइजी.......................................
आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देने वाली समिति के...........
एमएसएमई क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित..............
खादी को बतौर युनिफॉर्म अपनाएगी जे.के.सीमेंट्स............................
"खादी" को देश-विदेश में प्रमोट करेंगी फैशन क्वीन रितू बेरी.................
एयर इंडिया ने आयोग से खादी वस्त्रों एवं अन्य उत्पादों के आपूर्ति...............
एमएसएमई सचिव द्वारा केन्द्रीय मधुमक्खीपालन प्रशिक्षण केन्द्र, पुणे.............
एम.डी.टी.सी, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में एक दिवसीय हिन्दी.........
गांधी दर्शन, राजघाट में सोलर चरखे का प्रदर्शन..............................
आयोग के माध्यम से नगरोटा, जम्मू में उग्रवाद प्रभावित परिवारों को...........
दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु आयोग की.............
आयोग मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन.....................
अब शुक्रवार को सरकारी कर्मचारी पहनेगें खादी..............................
अनन्थपुरी में खादी फेस्ट 2016 खादी फैशन शो ने युवाओं को किया..........
बंगलुरु का सिटी स्कूल करेगा सप्ताह में एक दिन खादी वस्त्र का उपयोग........
अहमदाबाद में कताई-बुनाई कारीगर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह..............
खादी क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु स्थापित होंगे सोलर चरखे.......................
बायोगैस पर जागरूकता कार्यक्रम..
अंबाला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरूकता..........
वाराणसी में हिंदी कार्यशाला आयोजित......................................
आयोग के आंचलिक एवं राज्य कार्यालय, कोलकाता में हिन्दी.................

छाया चित्र पृष्ठ...09,16,17,20,24 एवं 25

एमएसएमई मंत्री महोदय द्वारा नागालैंड में खादी प्लाजा के लिए 6 करोड़ रुपये की घोषणा

दीमापुर (नागालैंड), 27, फरवरी 2016: केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री कलराज मिश्र ने दीमापुर स्थित छुमूकेदिमा पुलिस परिसर के रोडोडेन्ड्रोन हॉल में "क्षेत्रीय एमएसएमई कॉनक्लेव" का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कलराज मिश्र ने दीमापुर में एग्री एक्सपो साइट पर "खादी प्लाजा" स्थापित करने के लिए 6 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 'दीमापुर कॉन्क्लेव 2016' मंत्रालय की कार्यान्वित योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तथा इसके साथ ही राज्य सरकारों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के संघों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने में भी मदद करेगा तथा सरकार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के निष्पादन में भी सहायता होगी।

सम्मेलन में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा थे।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के महत्व पर बल देते हुए श्री मिश्र ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमो के संवर्धन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जबकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और उसके संगठनों की भूमिका उद्यमशीलता, रोजगार और आजीविका को प्रोत्साहित करना और बदले आर्थिक परिवेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

श्री मिश्र ने बताया कि विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का क्रियान्वयन एवं नीतियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का समर्थन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा।

वर्ष 2015-16 (31 जनवरी तक, 2016) के दौरान, 29,174 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे 2,11,601 कुल रोजगार उत्पन्न हुआ है। इसमें से 5092 परियोजनाओं को 8 पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) के लिए अनुमोदित किया गया है और इनसे 20639 रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है।

नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री टी.आर.जेलियांग ने आकड़ों की ओर संकेत करते हुए कहा की पूर्वोत्तर राज्यों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में देश के कुल सकल उत्पादन का केवल 1.78 प्रतिशत है जो राष्ट्र स्तरीय तय निवेश से दो प्रतिशत कम हैं। यहाँ कई कारकों के कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में उत्पादन और निवेश इतना कम हैं। यहाँ पर आधारभूत संरचना की कमी तथा भौतिक और वित्तीय बाधाएं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को विकसित करने में सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य संसदीय सचिव श्री अमेनबा यादेन ने कहा कि राज्य ने यहाँ एक खादी प्लाजा के निर्माण के लिए 6.18 करोड़ रूपये का परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने निधि के लिए सहमति जताई है।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक ने कहा कि हालांकि इस योजना के संशोधन को देखते हुए परियोजना को आज तक वित्त पोषित नहीं किया जा सका है और नागालैंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं उठा पाया है। उन्होने आगे बताया कि मंत्रालय द्वारा यदि उपयुक्त रूप से पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी तो राज्य से बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। बैंकों द्वारा मार्जिन मनी की मंजूरी में देरी से परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है। उन्होंने कहा कि 8.50 करोड़ रु. मार्जिन मनी के दावे बैंक में लंबित हैं, लक्ष्य अपर्याप्त हैं, जिससे राज्य की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जा सकता है।

इस क्षेत्रीय सम्मेलन में मिजोरम के उद्योग मंत्री श्री रोहलुना सहित अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नागालैंड राज्य के विधायक और अधिकारी भी इस अवसर पर उपलब्ध थे।

इसके पश्चात नागाओं के व्यापार एसोसिएशन ने भी केंद्रीय मंत्री का सम्मान किया और नई पीढ़ी के व्यापार समुदाय को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री ने अवसर पर बोलते हुए कहा कि उनके इस अनुरोध पर शीघ्र विचार किया जाएगा और यह नागालैंड के नए आर्थिक युग में प्रवेश की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (डिक्की) के पांचवें राष्ट्रीय औद्योगिक और व्यापार मेले का उद्‌घाटन

स्टैण्ड-अप इण्डिया पहल के तहत 2.5 लाख दलित उद्यमी खड़े किये जाएंगे

मुंबई: मार्च 25, 2016 : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये स्टैंड अप इंडिया पहल के तहत लगभग 2.5 लाख अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को तैयार किया जाएगा। दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (डिक्की) द्वारा आयोजित 5वें राष्ट्रीय औद्योगिक और व्यापार मेले के उद्‌घाटन समारोह में बोलते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि स्टैंड अप इंडिया पहल के तहत 1.25 लाख बैंक शाखाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से एक अनुसूचित जाति (एससी), जनजाति (एसटी) और एक महिला उद्यमी को वित्तपोषण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि देश में 2.5 लाख नए उद्यमी विकसित किए जा सकें।

श्री मिश्र ने कहा कि नवोन्मेष आधारित नई कंपनियों (स्टार्टअप) को मदद के लिए एक विशेष ढांचा होगा, जिसमें सरकार से वित्तपोषण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार नया उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के

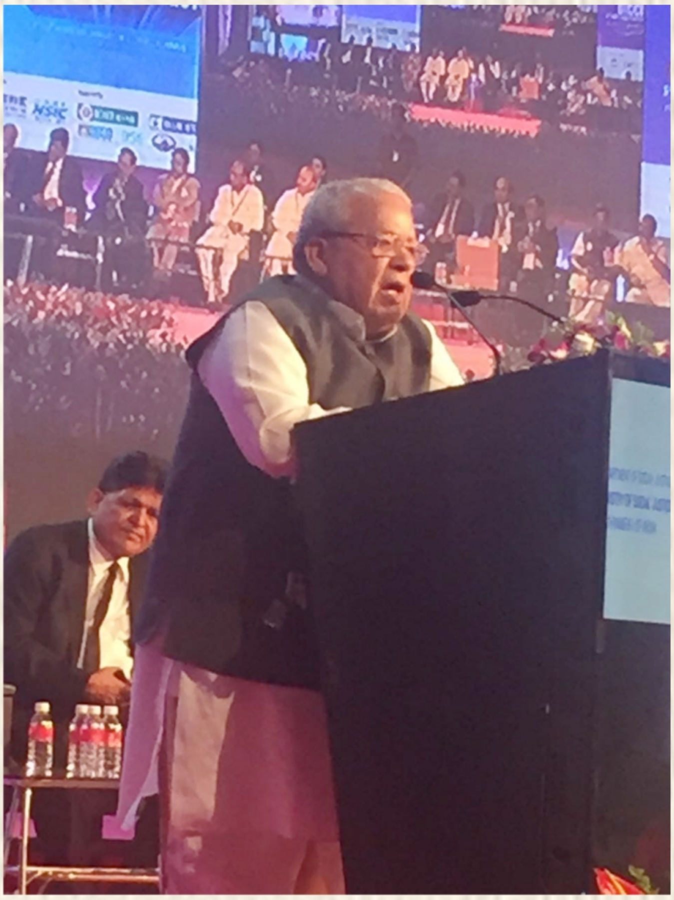

उद्देश्य से स्टार्टअप के लिए एक खाका (ब्लूप्रिंट) की शीघ्र ही घोषणा करेगी। सरकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (पीएमईजीपी) जैसे कई कार्यक्रम संचालित कर रही है।

श्री कलराज मिश्र ने आगे कहा कि पर्याप्त ऋण की उपलब्धता हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रही है और एमएसएमई मंत्रालय ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय, देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में रोजगार के सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना जैसे, प्रमुख कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को छूट प्रदान कर रहा है। शहरी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को, मार्जिन मनी सब्सिडी परियोजना लागत का 25 प्रतिशत प्रदान की जाती है, जबकि यह ग्रामीण क्षेत्रों में 35 फीसदी है, श्री मिश्र ने बताया।

एमएसएमई मंत्री ने यह भी कहा है कि दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (डिक्की), सशक्तिकरण के एक साधन के रूप में दलित उद्यम को सुविधाजनक बनाने के लिए दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रहा है और यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि दलित समुदाय, देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें, और जिससे वह रोजगार दाता बनें, ना कि नौकरी ढूँढने वाले बनें।

इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री श्री अनंत गीते ने कहा कि दलित उद्यमियों के लिए आशातीत मार्ग आगे है। उन्होंने बताया कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 292 उपक्रमों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र से अपनी जरूरतों का 20 प्रतिशत की खरीद के लिए अनिवार्य किया गया है, इसमें से 4 प्रतिशत दलित उद्यमों द्वारा की गयी है, जो एक बड़ा बाजार में तब्दील हुआ है।

इससे पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

यह औद्योगिक और व्यापार मेला, सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, गोरेगांव, मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 30 स्टालों सहित 350 स्टालों को लगाया गया था। उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण विषयों जैसे एमएसई खरीद नीति, बी 2 बी बैठकों पर, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि पर सेमिनार आयोजित किये गये, इसके अलावा व्यापार के अवसरों और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों को डिज़ाइन किया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सुशासन और रोजगार सृजन पर जोर

15 मार्च, 2016: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में सूचना प्रौद्यगिकी पर जोर दिया है ताकि सुशासन और रोजगार सृजन संभव हो सके। उन्होंने आज यहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के आला अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उद्योग आधार पर केन्द्रीय उद्योग आधार मैमोरेन्डम (यूएएम) उद्यमियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और हर दिन 4000 से अधिक यूएएम फाइल किये जा रहे हैं।

21 जनवरी, 2016 को सचिवों के समूह के साथ बातचीत के अंतिम सत्र में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज यहां मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सचिव समूह ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की कार्ययोजना के संबंध में दी गई रिपोर्ट के मद्देनजर निम्नलिखित बिंदु पेश किए थे:-

1.सुशासन-चुनौतियां और अवसर

2.रोजगार सृजन रणनीतियां

3.कृषि और सम्बंधित क्षेत्रों में किसान अनुकूल पहलें

4.शिक्षा और स्वास्थ्य-सार्वभौमिक सुगमता और गुणवत्ता

5.नवाचार संबंधी बजटीय प्रावधान और कारगर कार्यान्वयन

6.समावेश और समानता के आधार पर तीव्र वृद्धि

7.स्वच्छ भारत और गंगा संरक्षण लोगों की भागीदारी और निरंतरता

8.ऊर्जा कुशलता और संरक्षण

उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2018 तक सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल केबल के जरिये तेज गति की ब्रॉडबैंड सम्पर्कता के लिए कार्ययोजना के महत्व को दृष्टि में रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र ने मैदानी स्तर पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदमों की चर्चा की।

प्रस्तुतिकरण के दौरान श्री मिश्र ने कहा कि मंत्रालय की सूचना, शिक्षा और संचार योजना को जल्द अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि उद्यमियों को मंत्रालय की प्रक्रियाओं और नियमों की जानकारी हो सके।

(पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार)

वर्ष 2016-17 के दौरान 'पीएमईजीपी' के तहत 4,25,000 से अधिक नौकरियां सृजित की जाएगी

8 मार्च, 2016: केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री कलराज मिश्र ने कहा है कि 2016-17 और ज्यादा आवंटन एवं अपेक्षाकृत अधिक रोजगारों के सृजन के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए विकास वर्ष साबित होगा। श्री कलराज मिश्र ने कहा कि उनके मंत्रालय ने अपने लिए आवंटित 3,000 करोड़ रुपये के उपयोग और प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की है जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), स्फूर्ति, एस्पायर इत्यादि शामिल है।

यहां एमएसएमई मंत्रालय के रोडमैप और बजट आवंटन के बारे में जानकारी देते हुए श्री कलराज मिश्र ने कहा कि पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2016-17 के दौरान मार्जिन मनी के साथ 55,000 परियोजनाओं की सहायता के लिए 1,139 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जाएगा। इसकी बदौलत 4,25,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान खादी उत्पादन बढ़कर 1300 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने और 19.50 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसर सृजित होने की उम्मीद है। इस उद्देश्य के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग हेतु 341 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

श्री कलराज मिश्र ने कहा कि ग्रामीण कारीगरों के हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 60 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 39 क्लस्टरों (समूह) का विकास करने का फैसला किया है, जिससे 10,000 से ज्यादा कारीगर लाभान्वित हुए हैं।

श्री कलराज मिश्र ने कहा कि सरकार ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए बेहद उत्सुक है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण उद्योगों एवं उद्यमिता में नवाचार को बढ़ावा देने की योजना के लिए 100 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादन बढ़कर 45,000 करोड़ रुपये के स्तर को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे 163 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसर सृजित होने की आशा है।

श्री कलराज मिश्र ने कहा कि एनआई-एमएसएमई योजना, एमएसएमई क्लिनिक अवधारणा के साथ बन रही है। एमएसएमई के काम करने के विभिन्न पहलुओं पर कई विशेषज्ञ एमएसएमई क्षेत्र में एक छत के नीचे सभी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 500 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति / जनजाति के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है जिससे इस वर्ग के लोग नौकरी चाहने वाले नहीं बल्कि नौकरी प्रदाता

(शेष पृष्ठ 11 पर)

केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह खनवां में सोलर चरखे के लाभ के बारे में गोवा राज्य की महामहिम राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा से विचार विमर्श करते हुए।

हरिद्वार में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एन.आई.एस.सी. व एमएसएमई-डीआई के पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में संबोधित करते हुए केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह।

खादी के स्टोर को दी जायेगी फ्रेंचाइजी

हरिद्वार, 23 मार्च 2016: भारत सरकार की ओर से खादी को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंचाइजी दी जायेगी, यह बात केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने अपने हरिद्वार प्रवास के दौरान कही।

अपने प्रवास के दौरान श्री सिंह ने कहा कि खादी के प्रति युवाओं समेत अन्य लोगों में क्रेज बढ़ा है, लेकिन खादी आसानी से लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने बताया कि नामी कंपनियों के जगह-जगह शोरूम हैं, जहां से आसानी से पहुंचकर लोग खरीददारी कर सकते हैं। सरकार की योजना है कि विदेशी कम्पनियों की तरह खादी की जगह जगह शोरूम खोले जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है। खादी से बने कपड़ों को बेहद आकर्षण बनाया जा रहा है। इसके लिए फैशन डिज़ाइनर की मदद ली जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर रितु बेरी को खादी का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है।

उन्होंने कहा कि अब बाज़ार में खादी की टी-शर्ट एवं जींस की भी बाजार में पहुंच है। दिल्ली की तरह खादी की टी-शर्ट एवं जींस उत्तराखंड में भी मिल सकेगी। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि खादी को बढ़ावा देने के लिए ई-मार्केटिंग की योजना शुरू की गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि खादी को बढ़ावा देने के लिए राज्यपाल व मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य मधुमक्खी पालन के लिए भी बेहतर है।

दिये जाएंगे सोलर चरखे

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि बिहार की तर्ज पर उत्तराखंड समेत देश के अन्य राज्यों में सोलर चरखे दिये जाने की योजना है। इससे खादी कारीगरों की आमदनी के साथ साथ खादी का उत्पादन भी बढ़ेगा। हाथ से चलने वाले चरखे पर जहां मात्र डेढ़हजार से दो हजार कमाई होती है, वहीं सोलर चरखे से 6000 से 9,000की कमाई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि 2022 तक 5 करोड़ लोगों को सोलर चरखा दिया जाएगा।

आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार देने वाली समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष, श्री विनय कुमार सक्सेना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए दिये जाने वाले प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। यह समिति केबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस उपलब्धि के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग,अध्यक्ष महोदय को अपनी हार्दिक शुभ कामनाएँ देता है।

(पृष्ठ 8 से आगे)

बने। इससे कम से कम 2.5 लाख उद्यमियों को फायदा होगा।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने कहा है कि सरकार ने विभिन्न उद्योग संगठनों के साथ मिलकर अपने मंत्रालय में एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब का गठन करने का प्रस्ताव दिया है। यह हब केन्द्र सरकार की प्रापण नीति 2012 के तहत, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और स्टैण्डअप इण्डिया पहल के दायित्वों को पूरा करने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करेगा।

श्री मिश्र ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 44 एडी के तहत प्रकल्पित कराधान योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई टर्न ओवर सीमा, मौजूदा 1.00 करोड़ से 2.00 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया है, जिसमें अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान स्टार्ट अप स्थापित करने के लिए 5 वर्षों में से 3 वर्ष तक लाभ पर 100 प्रतिशत कटौती, विनियम में निवेश, पूंजीगत लाभ कर को छूट देने का प्रस्ताव है।

उन्होंने यह भी कहा है कि अगली पीढ़ी के बीच उद्यमिता कौशल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सरकार ने बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रशिक्षण बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम 2,200 कॉलेजों, 300 स्कूलों, 500 सरकारी और 50 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक उद्यमी, विशेष रूप से देश के दूरदराज के हिस्सों के लोगों को ऋण बाजार से जोड़ा जाएगा।

(पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार)

स्टार्टअप एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील दी गई

एमएसएमई क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान

11 मार्च, 2016: सरकार ने स्टार्टअप एमएसएमई के लिए मानदंडों में ढील देने का निर्णय लिया है। निर्णय के मुताबिक, अगर एमएसएमई निर्धारित तकनीकी और गुणवत्ता मानकों के अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं की डिलीवरी कर सकते हैं, तो उनके लिए पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार से जुड़े मानदंडों में ढील दी जाएगी। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से 20 फीसदी की अनिवार्य सरकारी खरीद में स्टार्टअप एमएसएमई को भी भाग लेने में मदद मिलेगी। यह ढील भारत में स्टार्टअप के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु दी गई है, जो सरकार के एजेंडे में काफी ऊपर है।

सरकार के राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रबंधन मानकों/गुणवत्ता प्रौद्योगिकी उपकरण योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने इस साल के साथ-साथ अगले वित्त वर्ष के दौरान भी भारतीय उद्योग परिसंघ और परामर्श विकास निगम के सहयोग से दो अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन मिशनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। अगले वित्त वर्ष के दौरान एमएसएमई-डीआई और अन्य विशेषज्ञ संगठनों के माध्यम से देश भर में विभिन्न राज्यों में 100 जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। अगले वित्त वर्ष के दौरान महानगर स्तर की 4 कार्यशालाएं दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता में और राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

(पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार)

खादी को बतौर युनिफॉर्म अपनाएगी जे.के.सीमेंट्स

नई दिल्ली और एयर इंडिया के बाद जे.के. सीमेंट्स समूह ने अपने विभिन्न संयत्रों में अपने कर्मचारियों के लिए खादी को यूनिफॉर्म के तौर पर अपनाने का निर्णय लिया है, इसके साथ ही यह समूह देशभर में अपने स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थयों के यूनिफॉर्म के लिए भी खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करेगा।

कंपनी के सी.एम.डी. श्री यदुपदी सिंघानिया ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना को एक पत्र लिखकर कहा है कि जे.के. सीमेंट्स ने महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से आगमन के सौ वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि के तौर पर खादी को अपनाने का निर्णय लिया है। साथ ही यह फैसला किया कि उनके सयंत्रों में कर्मचारियों और विभिन्न स्थानों पर स्कूल व कॉलेजों में विद्यार्थियों के यूनिफार्म केवल खादी के होंगे एवं यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजली होगी।

■■

"खादी" को देश-विदेश में प्रमोट करेंगी फैशन क्वीन रितू बेरी

20 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत लोगों से इस अपील के साथ की थी कि वे खादी का कोई सामान जरूर प्रयोग में लाएं। अब उनकी यह अपील रंग दिखा रही है।

खादी को मौजूदा समय के बढ़ते फैशन के साथ किस तरह से जोड़ना है ताकि उसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया जा सके, इसकी जिम्मेदारी खादी ग्रामोद्योग आयोग ने एक खास कार्यक्रम में मशहूर फैशन आइकॉन रितु बेरी को सौंप दी। बता दें कि 20 सितंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम की शुरुआत लोगों से इस अपील के साथ की थी कि वे खादी का कोई सामान जरूर प्रयोग में लाएं। 'मेक इन इंडिया' थीम और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए की गई मोदी की इस अपील ने खादी को लोगों के दिलों में खासा पॉप्युलर कर दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में ही खादी की बिक्री करीब 88 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। अब दुकानों में खादी के रेडीमेड कपड़े 30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत तक बिकते हैं। ज्यादातर युवा इसे सोबर कलर और कम्फर्ट फैक्टर के कारण पहनना पसंद करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रिय खादी वैसे अब पहले की तरह सादी नहीं रही है। इसके साथ खूब एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। डिज़ाइनर्स खादी की मदद से नए फैशन ट्रेंड तलाश रहे हैं। कुछ समय पहले ही आया खादी डेनिम फैब्रिक युवाओं में खासा पॉप्युलर होता जा रहा है। यह फैब्रिक आम मिलने वाले डेनिम से थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है।

इस मटीरियल में आने वाले जैकेट, जीन्स और शर्ट्स कम्फर्ट व कूल स्टेटमेंट की वजह से काफी डिमांड में है। लड़के और लड़कियां, दोनों ही इसे खूब पहन रहे हैं। खादी की लोकप्रियता के इन बढ़ते आंकड़ों से खादी ग्रामोद्योग आयोग के भी हौसले बढ़े हैं। इस तरह वे युवाओं को खादी के और करीब लेकर आएंगे। इसी श्रृंखला में खादी को देश और विदेशों में ख्याति मिल सके इसके लिए रितु बेरी को बतौर खादी ग्रामोद्योग आयोग की एडवाइजर नियुक्त कर दिया गया है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद सुश्री मिनाक्षी लेखी व खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने रितु बेरी को नियुक्ति पत्र सौंपा।

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि रितु बेरी को कमीशन के साथ जोड़ने से न केवल खादी को फैशन में नया स्टाइल मिल सकेगा बल्कि देश के साथ विदेशों में भी खादी का सही से प्रचार हो सकेगा। उन्होंने बताया कि रितु बेरी कमीशन के साथ एडवाइजर के तौर पर एक साल तक जुड़ी रहेंगी।

एयर इंडिया ने आयोग से खादी वस्त्रों एवं अन्य उत्पादों के आपूर्ति करने पर अपनी सहमति दी

इस वर्ष भारत के प्रधान मंत्री एयर इंडिया के ऐसे विशेष विमान से अपनी प्रथम विदेश यात्रा करेंगे जिसमें सभी क्रू सदस्य खादी पहनेंगे। केबिन क्रू की महिलाएं खादी सिल्क की साड़ियाँ और पुरुष खादी का जोधपुरी बंदगला सूट और पैंट पहनेंगे।

एयर इंडिया ने यह निर्णय लिया है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आपूर्ति किए गए खादी सिल्क से केबिन क्रू के कपड़े तैयार होंगे जिससे खादी का प्रचार और उन्नयन होगा। यह व्यवस्था भारत के प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए एयर इंडिया के अति विशेष चार्टर विमान में की जा रही है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारी ने बताया है कि एयर इंडिया के केबिन क्रू सदस्य विशेष रूप से खादी सिल्क के वस्त्र धारण करेंगे और एयर इंडिया इस पर भी विचार कर रहा है कि उनकी उड़ानों की विशिष्ट श्रेणी में खादी उत्पादों को उपयोग में लाया जाएगा।

एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबन्धक निदेशक, श्री अश्वनी लोहानी ने बताया कि हमने निर्णय लिया है कि हम खादी वस्त्रों का प्रयोग करेंगे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के खादी उत्पाद उपयोग करने के अनुरोध के पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक इकाइयों ने खादी उत्पाद उपयोग में लाने की इच्छा जाहिर की है। एयर इंडिया ने विशेष रूप में वी.वी. आई.पी. उड़ानों के लिए खादी वस्त्रों को उपयोग में लाने के लिए अपनी सहमति दी है और कार्यकारी वर्ग के क्रू सदस्यों के लिए भी खादी वस्त्रों को उपयोग में लाने का अनुरोध किया गया है। इन खादी वस्त्रों की कीमत बाजार के अनुरूप ही है। उन्होंने आगे जानकारी दी कि एयर इंडिया ने, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बिज़नस वर्ग में यात्रा करने वाले यात्रियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का किट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस किट में अन्य सामग्रियों के साथ खादी मोइश्चराइज़र, खादी रोज फेसवॉश, खादी हस्तनिर्मित साबुन आदि शामिल किये जाएगें।

आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण कुमार झा ने बताया कि विगत छः दशकों से खादी के उत्पादों की बिक्री में औसतन छः प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। विगत एक वर्ष से खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अब इस बिक्री में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यह आयोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। खादी की मांग में दिन प्रति दिन वृद्धि हो रही है । उन्होंने आगे बताया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग गत एक वर्ष से इस धारणा को दूर करने की कोशिश कर रहा है कि खादी केवल बुजुर्ग लोगों एंव राजनीतिज्ञों के लिए है।

प्रधान मंत्री ने जनवरी में अपनी मन की बात के माध्यम से लोगों को खादी को उपयोग में लाने का अनुरोध किया है जिससे महात्मा गांधी की यह परंपरा बनी रहेगी तथा इससे रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। अपने संबोधन में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "खादी क्षेत्र में बहुत से सरकारी संगठनों के प्रयास से लगभग 18 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि लोगों को अपनी अलमारी में कम से कम एक खादी का वस्त्र रखना चाहिए।" एयर इंडिया इस निर्णय पर सहमत है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एयर इंडिया को खादी वस्त्रों की आपूर्ति की जाएगी।

■■

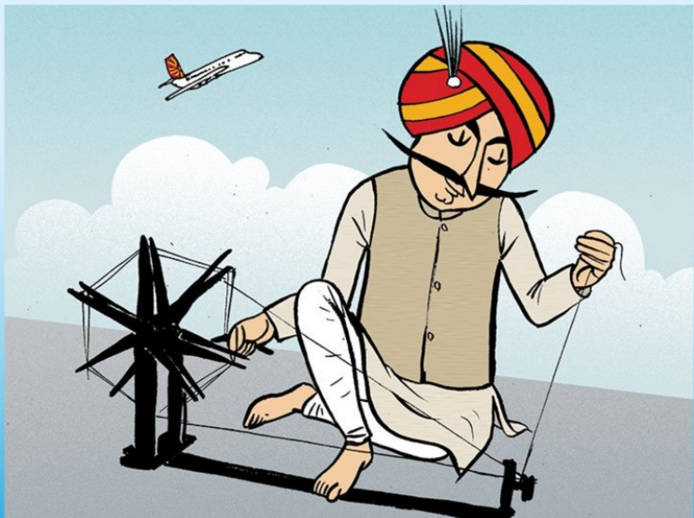

नई दिल्ली में, 14 मार्च, 2016 को राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री शम्भू दयाल बर्गुजर ने आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की।

04 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में संपन्न एक बैठक में आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना, राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री खलील रहीम को खादी वस्त्र भेंट स्वरूप प्रदान करते हुए।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलन में नरसन्नापेटा संघम के कॉमन फैसिलिटी सेन्टर का उदघाटन करते हुए आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना।

एमएसएमई सचिव द्वारा केन्द्रीय मधुमक्खीपालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे का निरीक्षण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री के. के. जालान ने 17 फरवरी, 2016 को केन्द्रीय मधुमक्खीपालन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, पुणे का दौरा किया। सुश्री शुभा मजूमदार, सहायक निदेशक प्रभारी सीबीआरटीआई ने सचिव का स्वागत किया। इस प्रवास के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग मुख्यालय, मुंबई के निदेशक श्री पी. आर. ब्राह्मणे उनके साथ थे।

श्री के.के. जालान ने सुश्री शुभा मजूमदार, और श्री पी.आर. ब्राह्मणे के साथ केन्द्रीय मधुमक्खीपालन और प्रशिक्षण संस्थान के गतिविधियों के संबंध में विचार-विमर्श किया तथा सीमित कर्मचारियों के होते हुए भी सी.बी.आर.टी.आई. द्वारा की गई प्रगति एंव मधुमक्खीपालन प्रौद्योगिकी के विकास पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पुस्तकालय, संग्रहालय और सभी प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान मधुमक्खीपालन की विभिन्न प्रौद्योगिकी जैसे ए. सैरेना कोम्ब फाउंडेशन शीट का उत्पादन, विभिन्न शहद स्रोतों की पहचान एंव इनका एकत्रण, शहद परिक्षण किटों के माध्यम से शहद का विश्लेषण, मधुमक्खी परागकणों का एकत्रण और मानव के लिए इसकी उपयोगिता, जंगली मधुमक्खियों से स्वास्थ्यवर्धक शहद का एकत्रण, शहद पार्लर का अवलोकन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपीस सैरेना और त्रिगोना मधुमक्खियों के आवास (कॉलोनी) का भी निरीक्षण किया और मधुमक्खियों के सम्पूर्ण जीवन तथा गतिविधियों के संबंध में जानकारी हासिल की। बी-कॉलोनियों का निरीक्षण करते समय मधुमक्खी पालन के बारे में भी उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने अपने सम्पूर्ण निरीक्षण के दौरान संस्थान के सभी गतिविधियों का उत्सुकतापूर्वक अवलोकन किया तथा कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया और प्रशिक्षणार्थी जो शहद प्रशिक्षण किट उपयोग में लाते हैं उनके साथ भी विचार-विमर्श किया।

उन्होंने, सी.बी.आर.टी.आई. के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा की व उन्होंने संस्थान में अनुसंधान करने और अन्य गतिविधियों का संचालन करने का भी सुझाव दिया।

गांधी दर्शन, राजघाट में सोलर चरखे का प्रदर्शन

श्री के. के. जालान, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बी.एच. अनिल कुमार के साथ दिनांक 29.02.2016 को दिल्ली स्थित आयोग के बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, गांधी दर्शन, राजघाट में सोलर चरखा प्रदर्शन केन्द्र का दौरा किया।

इस अवसर पर आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण कुमार झा ने सचिव एवं संयुक्त सचिव महोदय को सोलर चरखा प्रदर्शन केन्द्र में स्थापित सोलर चरखे के प्रदर्शन के बारे में सविस्तार से बताया। इस अवसर पर आयोग के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डा. नरेश पाल भी उपस्थित थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री के. के. जालान ने 26 मार्च, 2016 को आयोग मुख्यालय में खादी ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण कुमार झा, वित्तीय सलाहकार श्रीमती उषा सुरेश तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

आयोग के माध्यम से नगरोटा, जम्मू में उग्रवाद प्रभावित परिवारों को रोजगार

दिसंबर 2015 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री स्व श्री मुफ्ती मोहम्मद साहेब से एक मुलाकात की थी, जहां यह निर्णय लिया गया था कि जम्मू-कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित परिवारों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा।

उपरोक्त निर्णय के मद्देनजर, 257 महिलाओं को सिलाई का काम यूसुफ मेहरअली केन्द्र, नगरोटा (खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सीधे सहायता प्राप्त एक संस्था) के माध्यम से जम्मू जिले के नगरोटा गांव में रूमाल/नैपकिन का सिलाई कार्य, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली और संस्था के बीच हुए 1 मार्च 2016 से प्रभावी एक समझौते के आधार पर, दिया गया है। आयोग के इस प्रयास से इन महिलाओं को अपनी शून्य आय से, अब लगभग 200/ रुपये प्रति दिन की आमदनी होने लगी है।

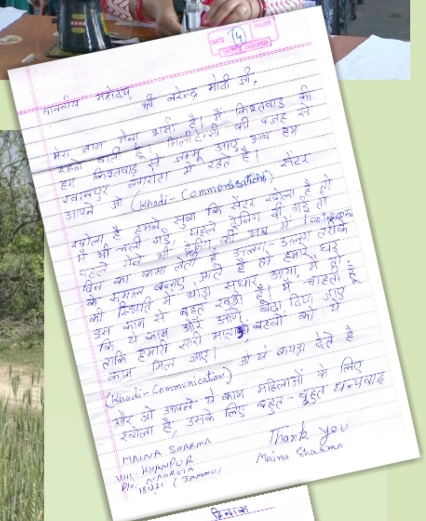

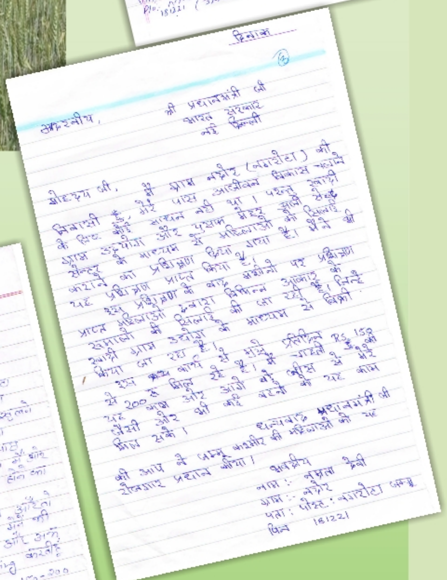

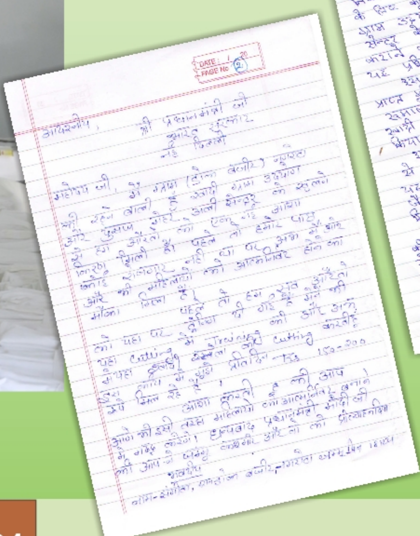

दिल्ली में मुस्लिम महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हेतु आयोग की नई पहल

उत्तर-पूर्व दिल्ली के चांद बाग क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम परिवारों ने समूहिक रूप में प्रधान मंत्री जी को हस्त लिखित पत्र भेजा जिसमें उनके कार्यों की सराहना करते हुए लिखा है:-

हमारा परिवार इस बात से बहुत ही प्रसन्न हैं कि उन्हें खादी और ग्रामोद्योग आयोग से निधीयन के साथ गैर-सरकारी संगठन के द्वारा प्रारम्भ किये गये दर्जी कार्यक्रम के अंतर्गत उनकी महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार की सुविधा प्रदान की गई है।

57 महिलाओं ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लेने के पश्चात उन्होंने सिलाई कार्य शुरू किया और ये महिलाएं नैपकिनों की सिलाई करके प्रति दिन 200/- रू अर्जित कर रही हैं। प्रत्येक महिला प्रति दिन 100 नैपकीन की सिलाई करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग उन्हें नैपकीन के आकार के अनुसार 1.50/- रूपये से 2.00/- रूपये तक प्रति नैपकीन प्रदान करता है। इन नैपकिनों की बिक्री, बिक्री केन्द्र के माध्यम से की जाती है और बहुत से होटलों एंव कॉर्पोरेट में उपहार के रूप में, या थोक में आपूर्ति की जाती है। इस परियोजना की शुरूआत मार्च, 2015 में की गई थी।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना ने व्यक्तिगत रूप में इस परियोजना की पहल की है

और इसका पर्यवेक्षण स्वयं भी किया है।

12वी पास सुल्ताना ने प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करते हुए कहती हैं कि इससे मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं चाहती हूं कि देश के विभिन्न भाग में मेरे दूसरे भाई और बहन भी इससे लाभान्वित हों।

रिजवाना ने अपने पत्र में लिखा है कि इस मदद के माध्यम से मैं अपने परिवार को आर्थिक मदद करती हूं एवं इससे मुझे समाज में पहचान मिली है।

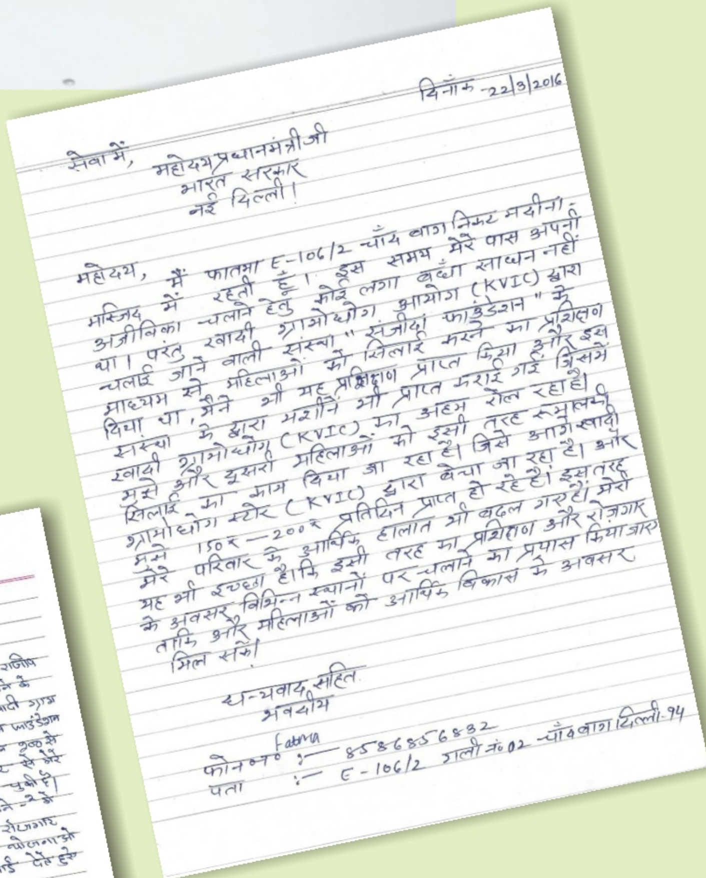

दिनांक-22/3/2016

सेवा में,
महोदय प्रधानमंत्री जी
भारत सरकार
नई दिल्ली।

महोदय, मैं फातमा E-106/2 चाँद बाग निकट मदीना मस्जिद में रहती हूँ। इस समय मेरे पास अपनी आजीविका चलाने हेतु कोई लगा बंधा साधन नहीं था। परंतु खादी ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा चलाई जाने वाली संस्था "संजीदा फाउंडेशन" के माध्यम से महिलाओं को सिलाई करने का प्रशिक्षण दिया था, मैंने भी यह प्रशिक्षण प्राप्त किया और इस संस्था के द्वारा मशीनें भी प्राप्त कराई गई जिसमें खादी ग्रामोद्योग (KVIC) का अहम रोल रहा है मुझे और दूसरी महिलाओं को इसी तरह रुमाल की सिलाई का काम दिया जा रहा है जिसे आगे खादी ग्रामोद्योग स्टोर (KVIC) द्वारा बेचा जा रहा है। और मुझे 150₹—200₹ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। इस तरह मेरे परिवार के आर्थिक हालात भी बदल गए हैं। मेरी यह भी इच्छा है कि इसी तरह का प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर विभिन्न स्थानों पर चलाने का प्रयास किया जाए ताकि और महिलाओं को आर्थिक विकास के अवसर मिल सकें।

धन्यवाद सहित
भवदीय
Fatima
फोन नं० :— 8586856832
पता :— E-106/2 गली नं० 02 चाँद बाग दिल्ली-94

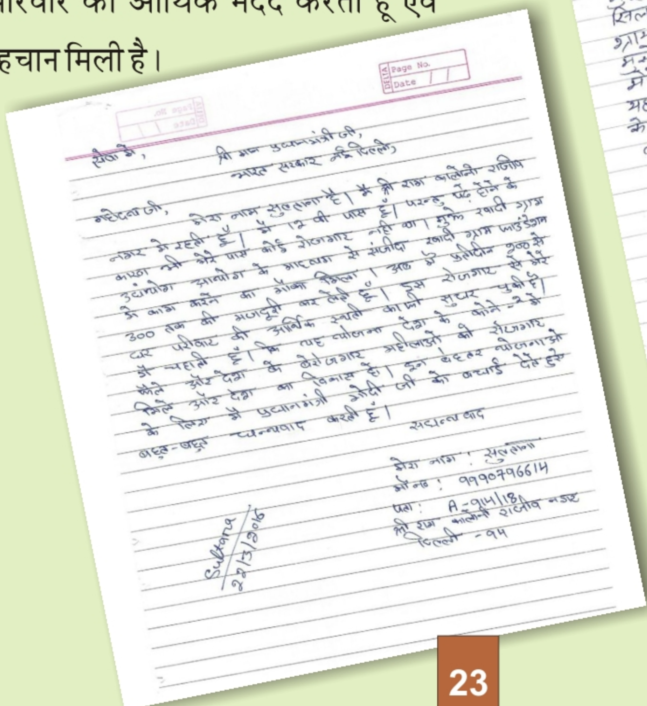

Page No.
Date / /

सेवा में,
श्री मान प्रधानमंत्री जी,
भारत सरकार नई दिल्ली,

महोदय जी,
मेरा नाम सुल्ताना है। मैं श्री राम कालोनी राजीव नगर में रहती हूँ। मैं 12 वी पास हूँ। परन्तु पढ़े होने के बाद भी मेरे पास कोई रोजगार नहीं था। मुझे खादी ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से संजीदा खादी ग्राम फाउंडेशन में काम करने का मौका मिला। अब मैं प्रतिदिन 200 से 300 तक की मजदूरी कर लेती हूँ। इस रोजगार से मेरे घर परिवार की आर्थिक स्थिति काफी सुधर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि यह योजना देश के कोने-2 में फैले और देश के बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिले और देश का विकास हो। इन बेहतर योजनाओं के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

सधन्यवाद

मेरा नाम : सुल्ताना
मो० नं० : 9990796614
पता : A-914/18 श्री राम कालोनी राजीव नगर दिल्ली-94

Sultana
22/3/2016

नई दिल्ली में पी.एच.डी.चैम्बर द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2016 को आयोजित स्टार्ट-अप समिट 2016 में संबोधित करते हुए आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरूण कुमार झा।

समिट का एक अन्य दृश्य।

आयोग मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैश्विक रूप में मनाया जाने वाला ऐसा उत्सव है जो महिलाओं की सामाजिक से राजनीतिक क्षेत्र तक अर्जित की जाने उपलब्धियों और लैंगिक समानता की भावना को उजागर करता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय, मुंबई में 8 मार्च, 2016 को यह दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में "आंतरिक ऊर्जा का आत्मसात" विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन आयोग की सभी महिला कर्मचारियों के लिए ढेबरभाई सभागृह में किया गया। इस विषय की वक्ता सुश्री मानसी ब्रह्मभट्ट, प्राणिक आरोग्य की अधिकृत प्रशिक्षक उपस्थित थीं।

कार्यक्रम का उद्घाटन खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय सलाहकार सुश्री उषा सुरेश द्वारा किया गया। आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अरुण कुमार झा और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री के. एस. राव ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर सभी महिला कर्मियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

इस अवसर पर मुख्य वक्ता सुश्री मानसी ने विषय पर बोलते हुए बताया कि किस प्रकार प्राणिक हीलिंग के द्वारा शारीरिक और मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है तथा मन और आत्मा को शांति का अनुभव होता है। सभी प्रतिभागियों ने व्याख्यान सत्र का लाभ उठाया।

अब शुक्रवार को सरकारी कर्मचारी पहनेगें खादी

नई दिल्ली: सरकारी कर्मचारियों के लिए अब शुक्रवार का महत्व बढ़ जाएगा। उन्हें अब हर शुक्रवार को खादी पहनकर दफ्तर जाना पड़ सकता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि देशभर में खादी उत्पादन को बढ़ावा देने और छोटे-छोटे बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी कर्मचारी हफ्ते में कम से कम एक बार खादी के कपड़े अवश्य पहनें। सरकार इस निवेदन पर विचार कर रही है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. सक्सेना ने बताया है कि वह सरकार के साथ इस योजना पर विचार कर रहे हैं और वह लोगों से भी खादी के उपयोग की अपील करेंगे। इस योजना को अनिवार्य ना बनाकर, स्वैच्छिक रहने दिया जाएगा, लेकिन लोगों से इस तरह की अपील करने से खादी की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि अगर हर कोई खादी से बना केवल एक भी कपड़ा खरीदता है, तो इसकी बिक्री में काफी बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार में इस समय 35 लाख कर्मचारी हैं। इनमें रेलवे और रक्षाकर्मी शामिल नहीं हैं। अधिकारी भी इस योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग, फैब इंडिया और रेमंड जैसी कम्पनियों के साथ मिलकर उच्च गुणवता के खादी बेचने की योजना बना रहा है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद भी खादी का काफी उपयोग करते हैं। उन्होंने कई बार लोगों से खादी खरीदने की अपील भी की है। इसके कारण खादी की बिक्री में इजाफा हुआ है। अब आयोग के लिए अपना उत्पादन बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है।

आयोग सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्कूल ड्रेस, रक्षाकर्मियों की वर्दी, रेलवे व एयर इंडिया में भी खादी के इस्तेमाल पर जोर देने की अपील कर रहा है। श्री सक्सेना ने कहा है कि हमें दान नहीं चाहिए। हम बाकी कंपनियों के साथ कीमत और गुणवता के आधार पर मुकाबला करेंगे। खादी ने हाल ही में रेलवे का एक 40 करोड़ रू. का टेंडर हासिल किया है। उन्होंने बताया कि जे.के. सीमेंट की तरह कुछ और निजी कंपनियों ने भी पूरी तरह से खादी के बने यूनिफॉर्म अपनाने का फैसला किया है।

श्री सक्सेना ने बताया कि उत्पादन बढ़ाना उनकी वरीयता है। वह वस्त्र उत्पादन में खादी की हिस्सेदारी को 1 फीसदी से बढ़ाकर 3.35 फीसदी तक ले जाना चाहते है। आयोग वर्तमान में अपने उत्पादन में 7 फीसदी से ज्यादा इजाफा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

राजीव गांधी अभियांत्रिकी कॉलेज, जुहु, मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जन शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री के.एस. राव एवं श्री वाय. के. बारामतीकर तथा निदेशक, प्र.मं.रो.सृ,कार्यक्रम श्रीमती प्रज्ञा जोगलेकर ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोग के पदाधिकारियों ने कॉलेज के छात्रों को प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार की असीम संभावनाओं के बारे अवगत कराया।

अनन्थपुरी में खादी उत्सव-2016

खादी फैशन शो ने युवाओं को किया आकर्षित

त्रिवेंद्रम, 27 फरवरी 2016: ऐपरेल प्रशिक्षण और डिजाइन केन्द्र, ऐपरेल पार्क, त्रिवेन्द्रम ने अनन्थपुरी खादी उत्सव 2016, राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी में एक खादी फैशन शो-निसर्ग 2016 का आयोजन किया।

इस उत्सव में विभिन्न डिजाइनों के अलग अलग श्रेणियों की साड़ियाँ तथा महिलाओं और पुरुषों के लिए खादी

की कुर्तियां तथा कुर्ते भी प्रदर्शित किए गए थे।

बच्चों सहित 50 मॉडलों ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया जिन्होंने ऐपरेल प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र, त्रिवेन्द्रम के विद्यार्थियों द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों में रैंप वॉक किया। इस खादी फैशन शो में मॉडलों और बच्चों द्वारा 10 राउंड में 100 किस्म के खादी वस्त्रों को प्रदर्शित किया गया ।

इस फैशन शो के उदघाटन अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग, त्रिवेन्द्रम के सहायक निदेशक श्री एम. चिन्नथंबी ने उपस्थित दर्शकों से खादी का उन्नयन करने की अपील की। इस कार्यक्रम में बहु उद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र की प्राचार्य श्रीमती वी.आर. सुसा एंव खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित भी थे।

इस कार्यक्रम में प्रदार्शित किये गये परिधानों को सर्वोदय संघ के खादी बिक्री केन्द्र, त्रिवेन्द्रम द्वारा तैयार करवाया गया था। त्रिवेन्द्रम शहरवासियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर खादी परिधानों से सुस्सजित शाम का खूब लुफ्त उठाया।

बंगलुरु का सिटी स्कूल करेगा सप्ताह में एक दिन खादी वस्त्र का उपयोग

बंगलुरु: 18 मार्च, 2016: स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को आत्मसात करने के लिए बंगुलुरु के सिटी स्कूल ने निर्णय लिया है कि उनके स्कूल में प्रिंसिपल से विद्यार्थी तक प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में एक दिन बुधवार को खादी अवश्य पहनेगा।

श्री वानी एज़्युकेशन सेंटर ट्रस्ट, शहर में तीन स्कूलों का संचालन कर रही है। यह ट्रस्ट अपने स्कूलों में आगामी शैक्षणिक वर्ष से खादी वस्त्र उपयोग में लाएगें। स्कूल में लगभग 5,000 विद्यार्थी हैं। कृपया ध्यान दें कि सभी को बुधवार को खादी यूनिफ़ार्म पहनना अनिवार्य किया गया है। श्री वानी एज़्युकेशन सेंटर ट्रस्ट मैनेजमेंट ने हाल ही में अभिभावकों को भी इस संबंध में संदेश भेज दिया है।

श्री आर. एच. श्रद्धा प्रसाद, सचिव, श्री वानी एज़्युकेशन सेंटर ट्रस्ट ने बंगलुरु मिरर से कहा कि विद्यार्थियों को खादी वर्दी के रूप में नया ड्रेस कोड दिया जाएगा, जिससे उन्हें स्वतन्त्रता संग्राम के मूल्यों को आत्मसात करने में मदद मिलेगी।

श्री प्रसाद ने आगे बताया कि युवा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम और खादी के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखता है। विगत वर्ष में, हमने खादी बोर्ड के सहयोग से नि:शुल्क चरखे संवितरित करके अनेक गतिविधियों का आयोजन किया था। हम अब 50वे वर्ष में कदम रख रहे हैं। इसलिए हम इस गतिविधि की नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि तीन परिसरों-राजाजीनगर में रामावना, बासवेश्वरनगर में शवाना और मगदी रोड में हनुमावना स्कूल के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक दिन बुधवार को खादी वर्दी को अनिवार्य करने के अलावा खादी कारीगरों को भी सशक्त करने का भी लक्ष्य है, जो अपनी आजीविका के लिए चरखे द्वारा हाथ से सूत कताई का कार्य करते हैं।

श्री प्रसाद ने जानकारी दी कि उत्तर कर्नाटक के बहुत से परिवार खादी से अपना जीवनयापन करते हैं। हम खादी की खरीदी कर उनकी अर्जन शक्ति को बढ़ा सकते है, इस कार्य को करने में खादी बोर्ड, खादी वस्त्र की खरीदी पर हमें 40 प्रतिशत छूट दे रही है तथा इन खादी वस्त्रों को विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा ।

खादी स्वतंत्रता संग्राम में आत्मनिर्भरता का प्रतीक था और एक शक्तिशाली हथियार था। हमारे विद्यार्थियों को खादी के संबंध में प्रत्येक बुधवार को व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाएगा।

अहमदाबाद में कताई-बुनाई कारीगर सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन

खादी ग्रामोद्योग संघ समन्वय, राजकोट एवं जरी रेशम खादी ग्रामोद्योग संघ, सुरत द्वारा खादी ग्रामोद्योग शताब्दी वर्ष 1915-2015 के उपलक्ष में कताई-बुनाई कारीगर सम्मेलन एवं श्री मनुभाई महेता सम्मान समारोह का आयोजन 27 फरवरी 2016 को गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में आयोजित हुआ ।

इस समारोह की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल-आन्ध्रप्रदेश तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पूर्व अध्यक्षा सु.श्री कुमुद जोशी ने की, अतिथि विशेष के रुप में सुश्री इलाबेन भट्ट, कुलपति-गुजरात विद्यापीठ/ संस्थापक-सेवा, आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री देवेन्द्रकुमार देसाई, पूर्व मुख्य सचिव-गुजरात सरकार श्री प्रविणभाई लहेरी उपस्थित थे। इस अवसर पर गुजरात सरकार एवं भारत सरकार द्वारा सम्मानित कत्तिन-बुनकरों को खादी हुंडी स्वरूप में उपहार चेक से सन्मानित किया गया। गुजरात विद्यापीठ की कुलपति, श्री प्रविणभाई लहेरी, श्री देवेन्द्रकुमार देसाई ने इस अवसर पर प्रासंगिक उद्‌बोधन किया ।

आयोग की प्रमाणपत्र समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री मनुभाई महेता के खादी क्षेत्र में 90 वर्ष समाप्त होने के उपलक्ष में श्री रजनीकुमार पंड्या द्वारा लिखी गयी पुस्तक **सेवा पंथना सौना साथी मनुभाई मेहता** का विमोचन किया गया । इस अवसर पर ग्राम स्वराज ट्रस्ट द्वारा श्री वजुभाई शाह की पुण्यतिथि के उपलक्ष में श्री मनुभाई महेता का अभिवादन किया गया एवं उन्होंने, रुपये 75000/- का पुरस्कार दिया गया, जो कि श्री मनुभाई महेता ने उसमें कुछ राशि जोड़कर उपहार स्वरूप 1.00 लाख रुपये समाज सेवा के लिए वापस कर दिये । प्रतिभाव देते हुए श्री मनुभाई महेता ने बताया, इतने महानुभावों द्वारा मेरे प्रति दिये गये विचार ही मेरा प्रतिभाव है । इस अवसर पर कई संस्थाओं के प्रतिनिधि, राजस्थान संस्था संघ के श्री रामदास आदि ने श्री मेहता का अभिवादन किया ।

अध्यक्षीय वक्तव्य में सुश्री कुमुद जोशी ने बताया, मैं गाँधीवादी को नहीं गाँधीजन को मानती हूं । आयोग के कार्यकाल के दौरान भी मेरे यही विचार थे । मैंने इन कत्तिन बुनकरों की रोजगारी के कई विरोध के बाद भी बढ़ाने का फैसला किया है । खादी उत्पादन में सोलर पावर का उपयोग गांधीवादियों के विरोध के बावजूद पॉयलट प्रोजेक्ट के रुप में प्रारंभ किया था, आज सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय ले रही है जोकि अच्छी बात है। इससे हमारे कत्तिन बुनकरों की रोजगारी के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।

खादी क्षेत्र में परिवर्तन लाने हेतु स्थापित होंगे सोलर चरखे

खादी क्षेत्र में, पारंपरिक हस्त चालित कताई चरखा के स्थान पर सोलर-चालित चरखा को स्थापित करके एक नया परिवर्तन लाया जा रहा है। द हिन्दू अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में सोलर चरखे स्थापित करने हेतु एक वृहद प्रोजेक्ट की योजना बनायी जा रही है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उठाए गए इस प्रकार के कदमों का मुख्य उद्देश्य है कतिनों के कठिन परिश्रम को कम करके उत्पादकता में वृद्धि करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना।

सोलर चरखा की शुरूआत करने से कतिनों को कताई कार्य करने में आसानी होगी, उनके द्वारा नवीकरण सौर ऊर्जा उपयोग में लायी जाएगी जिससे उनके आय में भी वृद्धि होगी।

सोलर चालित चरखे के माध्यम से आठ घंटे में 75-90 हैंक (गुंडी) का उत्पादन किया जा सकता है जबकि हस्त चालित चरखे के माध्यम से 25-30 हैंक (गुंडी) का उत्पादन किया जाता है।

सोलर चरखे को उपयोग में लाने से एक अन्य लाभ यह भी है कि इससे कतिनों के कार्य करने के समय में भी बचत होगी।

इस संबंध में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मण्डलीय निदेशक, विशाखापट्टनम श्री के. ब्रहमजी राव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सोलर चरखा के माध्यम से सूत उत्पादन में 300 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है, इसके अतिरिक्त कारीगर प्रतिदिन 350/- रूपये से ज्यादा

अर्जित कर सकते हैं जबकि पारंपरिक चरखे के माध्यम से प्रतिदिन 140/- रूपये प्रतिदिन की आमदनी होती है।

इस दिशा में एक पाइलट प्रोजेक्ट के तहत प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात आधारित उद्योग भारती, गोंडल संस्था द्वारा 10 चरखे प्रदान किये गये हैं। प्रत्येक चरखे की लागत 72000/-रूपए है।

सौर चालित चरखे विभिन्न खादी संस्थाओं जैसे अनकपल्ली, टूनी, नरसन्नापेटा और विशाखापट्टनम में स्थापित किए गए हैं। आगे, कारीगरों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से अधिक से अधिक सोलर चरखे प्रदान किए जाएगें।

श्री राव ने बताया कि विशाखापटन में बड़ी खादी संस्थाओं के लिए 10 सोलर चरखा और छोटी संस्थाए जो मण्डलीय कार्यालय के अंतर्गत आती हैं ऐसी संस्थाओं को 5 सोलर चरखे उपलब्ध कराये जाएंगे।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा नया मॉडल चरखा की शुरुआत करने का मुख्य उदेश्य केवल दुगुना उत्पादन करना नहीं बल्कि गुणवतायुक्त सूत का उत्पादन पर ही अपना ध्यान केन्द्रित करना भी है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इसकी संभाव्यता को बढ़ाया जा सके और स्थायी रोजगार का सृजन हो सके।

बायोगैस पर जागरूकता कार्यक्रम

बीकानेर, राजस्थान: खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मंडलीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा नुहांड, बीकानेर में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री संत कुमार सरपंच ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

सह विकास अधिकारी, श्री अशोक कुमार संघवी ने इस अवसर पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा इसके लाभों के बारे में भी बताया। एक संयंत्र की लागत लगभग 20 से 22 लाख रुपए के आसपास है जिसमे 9000 रुपए सब्सिडी के रूप में प्रदान की जाएगी और पांच साल तक तकनीकी मार्गदर्शन नि:शुल्क दिया जाएगा।

अंबाला में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन

दिनांक 02.03.2016 को राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत आर्य महिला महाविद्यालय, अम्बाला छावनी मे एक ''जागरूकता शिविर'' का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 150 महिला विद्यार्थियों ने भाग लिया।

सर्वप्रथम उपस्थित विद्यार्थियों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारे में एक पावर प्वाईंट प्रैजेन्टेशन द्वारा जानकारी प्रदान की गयी। तदुपरांत कैप्टन अनिल कुमार, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, अम्बाला ने कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों की भूमिका की विस्तृत जानकारी दी।

श्री बालेश्वर प्रसाद, विकास अधिकारी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत पात्रता, धनराशि, प्रोजैक्ट बनाने, विपणन आदि के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले अन्य लाभों पर भी प्रकाश डाला।

श्री वी.के. नागर, राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अम्बाला छावनी ने योजना के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि यह योजना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र मे भी अपना योगदान दे रही है क्योंकि यदि कोई महिला योजना के अन्तर्गत स्वंय का उद्योग स्थापित करती है तो उसे स्वंय की अंशदान का केवल 5 प्रतिशत जमा कराना होता है एवं मार्जिन मनी सब्सिडी 5 प्रतिशत अधिक दी जाती है। उन्होंने बताया कि आज के दौर में युवाओं के लिए नौकरी के अतिरिक्त अनेकों विकल्प मौजूद हैं जिनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वरोजगार हेतु उद्योग लगाना भी शामिल है। अनेकों महिलांए इस योजना के अन्तर्गत स्वंय का उद्योग स्थापित कर न केवल स्वंय के लिए वरन् अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध कराने में सक्षम हुई हैं।

यदि कोई महिला अथवा पुरूष नौकरी की तलाश करता है तो नौकरी में निश्चित वेतन ही आय का साधन बनता है एवं सेवानिवृति के बाद वह नौकरी परिवार के किसी अन्य सदस्य को स्थानान्तरित नही की जा सकती जबकि स्वयं का उद्योग लगाने से कार्य अनुसार उद्यमी को असीमित आय की प्राप्ति हो सकती है एव वह उद्योग परिवार के किसी भी सदस्य को भी स्थानान्तरित किया जा सकता है। उन्होंने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को सुझाव दिया कि वह केवल नौकरी के भरोसे न बैठे रहें वरन् प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का लाभ उठायें। उन्होंने यह भी बताया कि योजना के अन्तर्गत ई.डी.पी. प्रशिक्षण, उत्पादों के विपणन में सहायता, घरेलू एवं अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में हिस्सा लेना जैसे अनेकों लाभ भी उद्यमियों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

श्रीमती नीनाबेदी, प्रधानाचार्य, आर्य महिला महाविद्यालय ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग को धन्यवाद देते हुए देते हुए कहा कि आयोग ने महाविद्यालय में जागरूकता शिविर आयोजित करके अपनी योजनाओं की जानकारी महिला विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम उनके महाविद्यालय में आयोजित किये जांए।

जागरूकता शिविर के अन्त में विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के बारे में अनेकों प्रश्न किये गये, जिनका विद्यार्थियों ने समुचित उत्तर दिया। विजेता विद्यार्थियों को चॉकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

आयोग के आंचलिक एवं राज्य कार्यालय, कोलकाता में हिन्दी कार्यशाला आयोजित

आंचलिक एवं राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, कोलकाता में दिनांक 10.03.2016 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें कार्यालय के कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सर्वप्रथम हिन्दी कार्यशाला का उद्घाटन सह निदेशक प्रभारी के द्वारा किया गया। जिसके साथ आंचलिक कार्यालय के सह निदेशक उपस्थित थे। मुख्य अतिथि तथा वक्ता के रुप में श्री प्रदीप श्रीवास्तव, हिंदी प्रध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, निजाम पैलेस, कोलकाता विराजमान थे।

सह निदेशक प्रभारी ने उपस्थित सभी कर्मचारियों को कार्यालय के कामकाज में हिंदी के प्रयोग तथा फाईलों में हिंदी में नोटिंग करने पर अपना वक्तव्य दिया। साथ ही सभी कर्मचारियों को निदेश दिया कि मुख्य अतिथि के दिए जाने वाले वक्तव्य को कार्यालयीन काम काज के प्रयोग में लाया जाए। इसके उपरान्त मुख्य अतिथि श्री श्रीवास्तव जी साहित्यिक भाषा, आंचलिक भाषा एवं कार्यालयीन भाषा के अन्तर संबंध को बताते हुए उपस्थित कर्मचारियों को पर्यटन का अनुभव पर 100 शब्दों में निबंध लिखने का कार्य दिया। उपस्थित कर्मचारीगण अपने-अपने पर्यटन/भ्रमण का अनुभव 100 शब्दों में लिखा। जिसे कार्यशाला में उपस्थित सभी कर्मचारियों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। साथ ही इनके लेखन शैली की प्रशंसा व्यक्त कर प्रोत्साहित किया।

अंत में, श्रीमती रीता राय, निम्न श्रेणी लिपिक के द्वारा कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मुख्य अतिथि को कार्यशाला के सफल आयोजन पर धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम का संचालन श्री प्रभु प्रसाद यादव, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक द्वारा किया गया।

■■

वाराणसी में हिंदी कार्यशाला आयोजित

दिनांक 31.03.2016 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मंडलीय कार्यालय, वाराणसी में अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्य की विशेषताओं को सीखने के लिए "हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया। हिंदी कार्यशाला के मुख्य वक्ता केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, नई दिल्ली के प्रतिनिधि (पूर्व सचिव, नराकास, वाराणसी) श्री जगदीश नारायन राय रहे। जिन्होंने बड़े ही सहजता से बताया कि कार्यालयीन कार्य हिंदी में करते समय आने वाली त्रुटियों को किस प्रकार दूर किया जाय। साथ ही साथ संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों से भी उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया और राजभाषा हिंदी का क्या महत्व है, इससे भी सभी को अवगत कराया।

हिंदी कार्यशाला में सर्वश्री महेन्द्र कुमार (संयोजक), आर.डी. वम, ओ.पी. सिंह, दिनेश सिंह, आर.पी. राय, बी.पी. पाण्डेय, के.पी. मिश्रा, एस.पी. सिन्हा आदि ने भी अपने विचार प्रकट किये। कार्यक्रम का संचालन श्री पी.के. दत्ता ने किया।

■

एम.डी.टी.सी, गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित

खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एम. डी. टी. सी, गांधी दर्शन, राजघाट , नई दिल्ली में 22.02.2016 को एक दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला एम. डी. टी. सी. में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित की गयी थी।

इस कार्यशाला का उद्देश्य एम. डी. टी. सी. कार्यालय के कर्मचारियों को दिन-प्रतिदिन के कार्यालयीन पत्राचार और प्रलेखन में राजभाषा के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला की अध्यक्षता एम. डी. टी. सी, गांधी दर्शन, राजघाट , नई दिल्ली के उप निदेशक, श्री नत्थूलाल ने की तथा नराकास, दिल्ली के सहायक महा प्रबन्धक, श्री अशोक शर्मा ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजभाषा पर व्याख्यान दिया।

स्थानीय प्रतिनिधि कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली के सहायक निदेशक, श्री डी. एस. भाटी ने भी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया।

सेवानिवृत्ति

श्री मिहिर पटेल

श्री मिहिर पटेल, अधीक्षक, राज्य कार्यालय, अहमदाबाद, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 29 फरवरी 2016 को स्वेच्छा से खादी और ग्रामोद्योग आयोग की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।

राज्य कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इस अवसर पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। वह अपने पिता श्री मनु भाई पटेल, तत्कालीन निदेशक, पीसीबीआई के निधन के बाद प्रतिपूरक आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग में नियुक्त हुए थे। श्री मिहिर को अपने काम में दक्षता और विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है।

खादी

स्वस्थ जीवन का प्राकृतिक मार्ग

बहुमुखी एवं मनमोहक खादी डिजाइनर
परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प

अपने नजदीकी खादी भवन/भंडार मे अवश्य पधारें

KVIC

कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056.
फोन : 022-2671 4320, 2671 6323
वेबसाईट : www.kvic.org.in